Module 4

विद्यालय प्रधानों के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम और वित्तीय प्रबंधन संबंधी जागरूकता

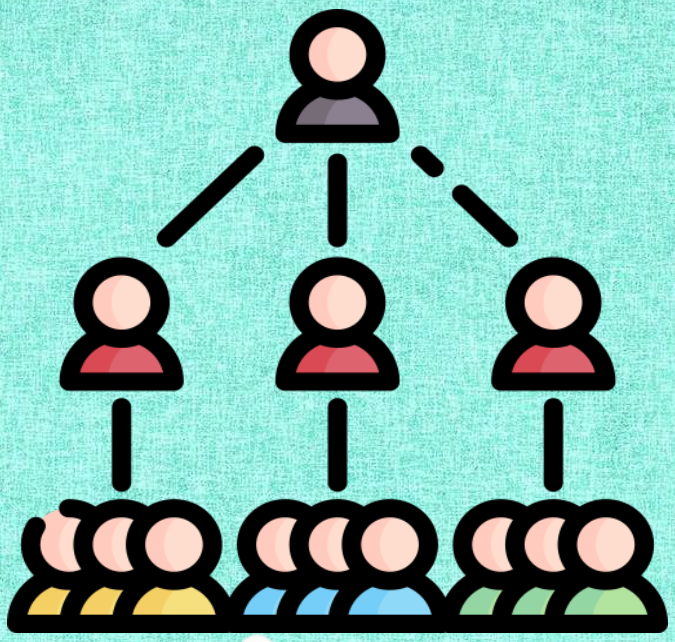

● रंजन कुमार ● हरिदास शर्मा

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज 'जुड़ाव और समन्वय' आवश्यक है।

"A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution., However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education".

अनुक्रमणिका

- प्रस्तावना
- उद्देशिका
- बिहार की विद्यालयी व्यवस्था में प्रशासनिक पदानुक्रम
- विद्यालय प्रधानों के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम का महत्व
- वित्तीय प्रबंधन संबंधित जागरूकता
- वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य
- वित्तीय प्रबंधन का दायरा

प्रस्तावना

सुविकसित समाज की परिकल्पना, एक सुविकसित व सुनियोजित विद्यालय से होकर गुजरती है और साकार होती है। वस्तुतः समाज की व्यापक संरचना के संदर्भ में हम देखते हैं कि उसके वैकासिक क्रम के निर्धारण में विद्यालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। स्कूलों में ही हमारी पीढियां सर्वप्रथम एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा लेती और सीखती हैं। विख्यात शिक्षा शास्त्री डील और पीटरसन ने इस संबंध में अपने विचार देते हुए कहा है कि एक अच्छा स्कूल, अपने शिक्षार्थियों के लिए न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है, बल्कि यह उनमें सहयोगात्मक निर्णय की क्षमता और उनके पेशेवर कौशलों के विकास के लिए सीखने हेतु निरंतर नए एवम उपयुक्त अवसरों को बढ़ावा भी देता है।

हम सभी अवगत हैं कि सुव्यवस्थित विद्यालय के लिए उसकी शासकीय संरचना का सुव्यवस्थित होना एक अनिवार्य घटक है, प्रायः ये देखा गया है कि वो विद्यालय ज्यादा सुव्यवस्थित होता है जो अपनी शासकीय संरचना के लिए श्रेणीबद्ध रूप में उच्चतर का अपने निम्नतर पर नियंत्रण और निम्नतर का अपने उच्चतर के प्रति जवाबदेही से युक्त पदानुक्रम वाली शासन व्यवस्था का अनुसरण करता है।

पदानुक्रम वाली व्यवस्था से संबंधित तथ्यों पर विस्तृत विमर्श से पूर्व, पदानुक्रम क्या है, क्यों आवश्यक है तथा इसकी उत्पत्ति आदि के स्त्रोत क्या हैं ये जान लेना आवश्यक है।

यथार्थतः 'पदानुक्रम' अंग्रेजी शब्द Hierarchy का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है किसी भी सांगठनिक/सांस्थानिक तंत्र/प्रणाली में शासकीय नियंत्रण के लिए निम्नतम से उच्चतम स्तर तक विशिष्ट रूप से निर्धारित पद सोपान।

अधिकांशतः विद्यालय व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के लिए ये शब्द भले अपरिचित सा लगे किन्तु कार्य निष्पादन के क्रम में प्रशासनिक रूप से विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित अर्हता अनुसार प्रदत्त कार्य-दायित्व, पद, वेतनक्रम व अन्य सुविधाओं से निरंतर उनका वास्ता पड़ते रहता है।

जब भी पदानुक्रम शब्द का संदर्भ सामने आता है तो यूरोपीय शासन तंत्र के पिरामिडनुमा ढांचे वाली शासकीय संरचना में नीचे से ऊपर परस्पर नियंत्रण व अनुपालन के प्रावधानों से समावेशित कार्मिकों का कार्यरत समूह, दृष्टिपटल पर स्वतः ही कौंध उठता है।

पदानुक्रम के सैद्धांतिक रूप का प्रथम प्रतिपादन मशहूर और मूल रूप से मानवतावादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम हैराल्ड मास्लो ने किया जो मूलतः मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध तरीके से रेखांकित करनेवाला था। मास्लो के अनुसार ' जब मानव की आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वह निरंतर ज्यादा उच्च जरूरतों की पूर्ति चाहता है और इसी तरह जरूरतों का एक पदानुक्रम विकसित हो जाता है। इसी आधार पर लोक प्रशासन में भी कार्य की प्रारंभिक आवश्यकता की पूर्ति से निरंतर आगे के कार्य जरूरतों का निर्धारण कर दायित्व वितरण के लिए पदानुक्रम का विकास किया गया।

जब हम विद्यालय स्तर पर पदानुक्रम की बात करते हैं तो आम तौर पर एक ऐसी प्रणाली उभरकर सामने आती है, जिसमें विद्यालय प्रमुख/प्रधानाध्यापक मध्य स्थिति की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं ; जहां एक ओर प्रधानाध्यापक से ऊपर नियंत्रक शक्तियों से लैस प्रखंड से जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक से आगे सभी शैक्षणिक सहायक और गैर शैक्षणिक सहायक तथा सभी कक्षाओं के वर्ग शिक्षक, बाल- संसद और कक्षा नायक/क्लास मॉनिटर सहित सभी शिक्षार्थी शामिल होते हैं।

बिहार की विद्यालयी व्यवस्था में प्रशासनिक पदानुक्रम का वर्तमान स्वरूप निम्नरूपेण वर्णित किया जा रहा है :-

विद्यालय से उच्चतर प्रशासनिक पदानुक्रम

माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ➔ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव ➔ विभाग के सभी निदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मी ➔ प्रमंडल स्तरीय अधिकारी और कर्मी ➔ जिला स्तरीय अधिकारी ➔ प्रखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मी ➔ स्कूल कॉम्प्लेक्स ➔ विद्यालय प्रशासन (प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक तथा अन्य सहयोगी कर्मी)

विद्यालय से निम्नतर प्रशासनिक पदानुक्रम

विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति/ विद्यालय शिक्षा समिति ➔ प्रधानाध्यापक ➔ उप प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक ➔ वर्ग अध्यापक/अध्यापक ➔ वर्ग नायक/ क्लास मॉनिटर ➔ शिक्षार्थी एवम अभिभावक।

उपर्युक्त पदानुक्रम के संदर्भ में ये तथ्य सदा स्मरण रखने योग्य है कि विद्यालय प्रमुख, उच्चतर पदानुक्रम वाली संस्थाओं एवम उच्चतर पद के अधिकारियों के प्रति जिम्मेवार होते हैं तथा उन्हें निम्नतर पदानुक्रम की संस्थाओं और निम्नतर पदधारियों पर नियंत्रण रखना होता है।

नियामक / नियंत्रक निर्देशों का प्रवाह

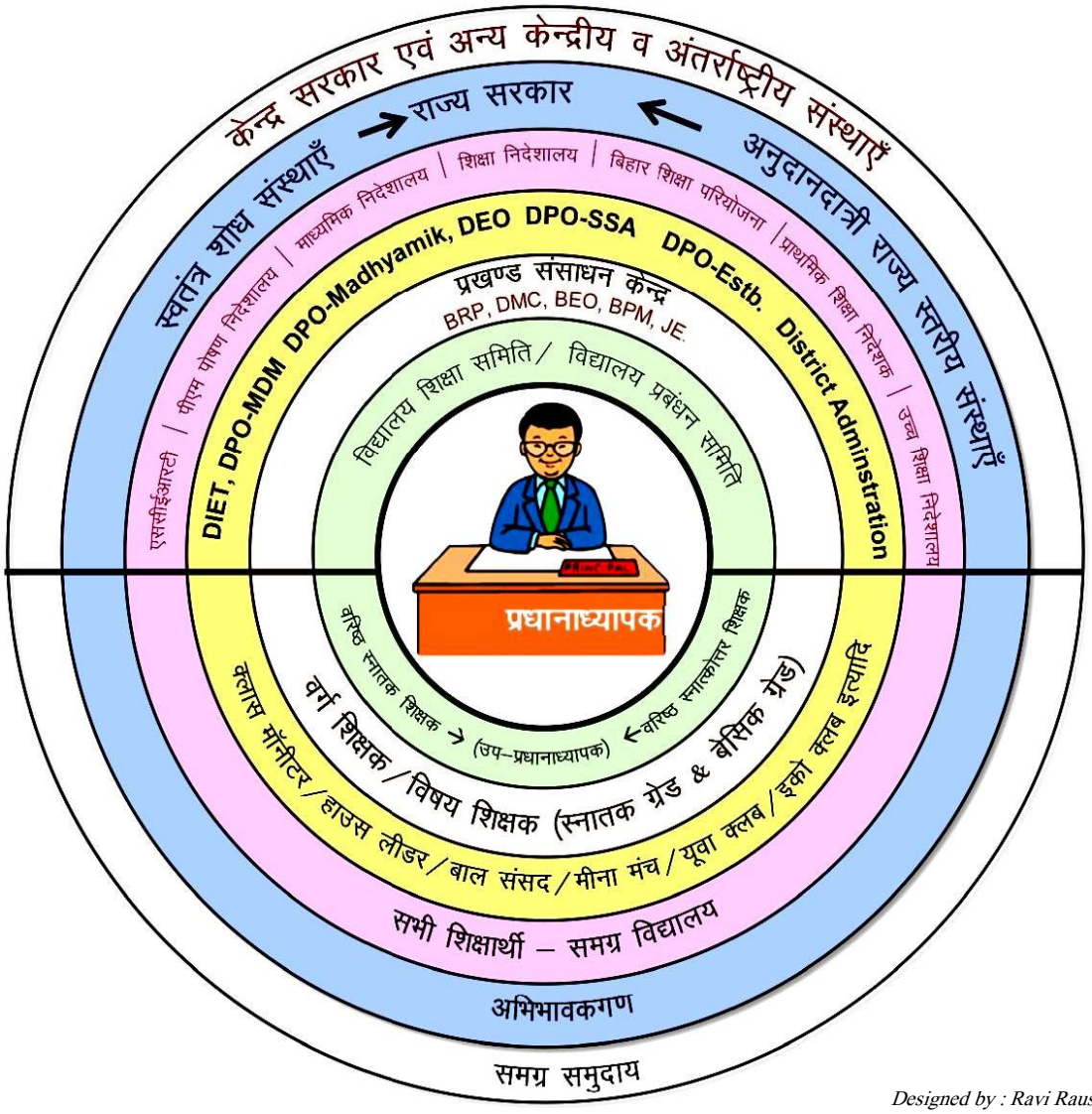

Designed by : Ravi Raushan Kumar

विद्यालय प्रमुख के रूप में प्रधानाध्यापक को निम्नांकित दायित्व निभाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है :-

1. शिक्षकों और अन्य सहकर्मियों के कार्यों का निर्धारण तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की देखरेख करना।
2. सरकार/विभाग के स्तर से जारी किए गए पाठ्यक्रम के मानकों को लागू करना।
3. कक्षा शिक्षण के लिए कार्यक्रम और कार्यसारिणी का निर्माण करना।
4. विद्यालय स्तर पर कार्य के बेहतर प्रबंधन के लिए नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं का निर्धारण करना।

5. शिक्षार्थियों के अधिगम लक्ष्य, अधिगम प्रतिफल और उपलब्धि से संबंधित आंकड़ों की नियमित तौर पर समीक्षात्मक निगरानी करना।

6. विद्यालय में शिक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए कार्य अनुशासन के मानक निर्धारित करना।

7. विद्यालय की वित्तीय जरूरतों के आकलन के साथ बजट तैयार करना।

8. आवश्यकतानुसार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अभिभावकों सहित अन्य सभी हितधारकों के साथ विभिन्न माध्यमों से संवाद कायम करना।

विद्यालय प्रधानों के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम का महत्व :-

1. किसी भी विद्यालय प्रधान के लिए विद्यालय स्तर पर पारदर्शी पदानुक्रम की व्यवस्था अपनाने से उन्हें विद्यालय प्रबंधित करना सुगम लगने लगता है तथा यह विद्यालय स्तर पर शिक्षकों और शिक्षार्थियों के विद्यालयी व्यवहार का नियमन तथा नियंत्रण काफी त्वरित एवम आसान बनाता है।

2. हर स्तर पर किसी भी समस्या को लेकर मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने निकटतम वरिष्ठ के पास ले जाने में कोई भ्रम या चिंता की कोई स्थिति दृष्टिगत नहीं होती है। सबों को अपने पदसोपान के सापेक्ष क्या, कब और कैसे करना है ये सबको पता रहता है।

3. पदानुक्रम की व्यवस्था के कारण शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए विद्यालय में लक्षित कार्य को पूर्ण करना तथा वांछित परिणाम को प्राप्त करना सुगमता की दृष्टि से स्पष्ट और आसान लगता है।

4. समस्याओं के उपचार तक आसान पहुंच; यदि किसी शिक्षक या छात्र को ऐसा लगता है कि वे किसी समस्यागत स्थिति या व्यवहार से निपटने में सक्षम नहीं हैं, तो वो विद्यालय स्तर पर लागू प्रशासनिक पदानुक्रम की व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने से ठीक ऊपर पद सोपान के प्राधिकृत व्यक्ति को यथावत अग्रेषित कर देने के लिए निर्देशित होते हैं। यह वास्तव में काफी प्रभावकारी होता है इसलिए भी कि हर कोई ये जान रहा होता है कि कौन कार्य किस स्तर पर और कैसे संपादित होंगे तथा उनसे संपर्क करने या उनसे मदद मांगने में खुद को सहज महसूस करेंगे।

5. गंभीर व्यवहार संबंधी घटनाओं के कुछ जटिल मामले आमतौर पर खुद के स्तर से जिस वरिष्ठ सदस्य के पास भेजे जाते हैं उसे यथासंभव अधिक जानकारी रखने की आवश्यकता होती है, ताकि वे सम्यक हस्तक्षेप करने के और समुचित निदान तक पहुंचने का निर्णय ले सकें। इससे व्यवहार को उन्नत करने के लिए एक मानकीकृत

प्रणाली बनाने में मदद मिल सकती है जो आगे बिना किसी व्यवधान के कक्षा की आवश्यकताओं की बात तथा अन्य किसी भी विवरण को खुद के स्तर से आगे संबंधित सदस्य तक पहुँचाया जा सके।

6. वरिष्ठता के अनुसार शिक्षकों और कक्षा नायकों का समर्थन और प्रोत्साहन की व्यवस्था; प्रायः ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि नए कक्षा शिक्षकों में अक्सर स्थापित संबंधों और अधिकार का अभाव होता है जो उनके वरिष्ठ सहयोगियों के पास होता है। सामान्य शिक्षण के दौरान यह एक कारक नहीं हो सकता है, लेकिन जब कोई गंभीर व्यवहार संबंधी घटना सामने आती है तो स्थिति को हल करने के लिए आवश्यक अधिकार के स्तर पर जोर देना उनके लिए अधिक कठिन हो सकता है। यहीं पर एक स्पष्ट पदानुक्रम काम आता है। यदि शिक्षकों को पता हो कि गंभीर घटनाओं को कैसे और कब उठाना है, तो इन घटनाओं से जल्दी और अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इससे न केवल अन्य छात्रों को लाभ होता है जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि इससे विघटनकारी छात्र को भी अधिक संरचित हस्तक्षेप से लाभ होता है। लेकिन इससे परे, इसका अधिक लाभ शिक्षकों को होता है तथापि कि इससे संबंधित व्यवधानों और व्यवहार संबंधी घटनाओं से निपटने का तनाव और अतिरिक्त कार्यभार वास्तव में कठिन हो सकता है, और काम के बढ़ते घंटों का दबाव शिक्षक के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

विद्यालय प्रधानों के लिए विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक पदानुक्रम के संदर्भ का मतलब केवल व्यवहार संबंधी घटनाओं से निपटने में पदसोपन के सापेक्ष परस्पर केवल मदद करना भर नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि जब भी विद्यालय प्रमुख /प्रधान को खुद से न्यून पदानुक्रम में अध्यापकों और छात्रों के साथ संवाद करने तथा उच्च पदानुक्रम में नीतिगत निर्णय की अधिकारिता रखनेवाले अधिकारियों को स्थितियां प्रतिवेदित किए जाने के संदर्भ आते हैं तो उनके साथ हमेशा सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने और उन्हें इस हेतु आश्वस्त करने की जरूरत भी होती है कि वे सही काम कर रहे हैं एवम इसी क्रम को नियमित रूप से सुव्यवस्थित काम करते हुए आगे अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

***

वित्तीय प्रबंधन सम्बंधित जागरूकता

विद्यालय के समग्र विकास में वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राय: सभी विद्यालयों में विभाग द्वारा विभिन्न मद जैसे- समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना अंतर्गत राशि निर्गत की जाति है जिसका समुचित प्रबंधन कर ही विद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

आय-व्यय में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही विद्यालय को अपनी आवश्यकतानुसार बजटीय प्रावधान का आकलन एवं योजना निर्माण के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना पड़ता है।

वर्तमान समय में वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है तथा अधिकांशतः लेन-देन डिजिटल रुप में संचालित किया जा रहा है।

अतः आवश्यकता है, विद्यालय को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की।

NEP-2020 एवं इक्कीसवीं सदी की वांछित योजनाओं पर दृष्टि डाली जाय तो विद्यालयों के लिए वित्तीय प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार किया जाए तो एक संस्था को कुशल वित्तीय प्रबंधन संबंधित जानकारियों से परिपूर्ण होना आवश्यक है, ताकि संस्था का समग्र विकास हो सके।

" वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णय लेने का एक क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उद्यम लक्ष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।" -

वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य

वित्तीय प्रबंधन जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन होता है। वित्तीय प्रबंधन साधारणतया किसी संस्था के वित्तीय संसाधनों की खरीद, आवंटन तथा नियंत्रण से संबंधित होता है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन की समझ का होना विद्यालय के लिए आवश्यक है ।

इसके निम्नांकित उद्देश्य है :-

- वित्तीय प्रबंधन की समझ विकसित करना
- विद्यालय को वित्तीय प्रबंधन हेतु सक्षम बनाना

- वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी एवं नियमानुसार संपादित करना
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित राशि का व्यय सुनिश्ति करना

- विद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार वित्तीय प्रबंधन हेतु संसाधन विकसित करना
- वित्तीय प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना
- संस्था / विद्यालय को धन की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना

वित्तीय प्रबंधन का दायरा

विद्यालय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन सम्बंधित कार्य विद्यालय को स्वयं करना पड़ता है ताकि विद्यालय का समग्र विकास हो सके। वित्तीय प्रबंधन संबंधी विद्यालय के निम्नांकित कार्य है :-

- वित्त संबंधी कार्य हेतु फण्ड जुटाना
- निवेश करना
- निवेश से अर्जित आय का समुचित उपयोग
- आय-व्यय का संतुलित क्रियान्वन

विद्यालय स्तर पर उपर्युक्त कार्यों को सम्पादित करने सम्बंधित जानकारी विभागीय स्तर एवं प्रशासनिक स्तर पर संस्था को उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, क्योकि अधिकांशतः विद्यालय जानकारी के आभाव में या विभागीय निर्देश की प्रतीक्षा में वित्तीय कार्य ससमय सम्पादित नहीं कर पाते है, ऐसे में जरुरी है की समय समय पर विद्यालय को वित्तीय जानकारी संबधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र

विद्यालय विभिन्न स्तर पर स्वयं वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक विद्यालय को सर्वप्रथम इससे संबंधी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। अपने संसाधन का किस प्रकार उपयोग कर धन एकत्रित करें तथा योजनाबद्ध तरीके से उसका व्यय कैसे किया जाये यह विद्यालय को निर्धारित करना होता है।

विद्यालय वित्तीय प्रबंधन निम्नांकित स्तर पर कर सकते हैं :-

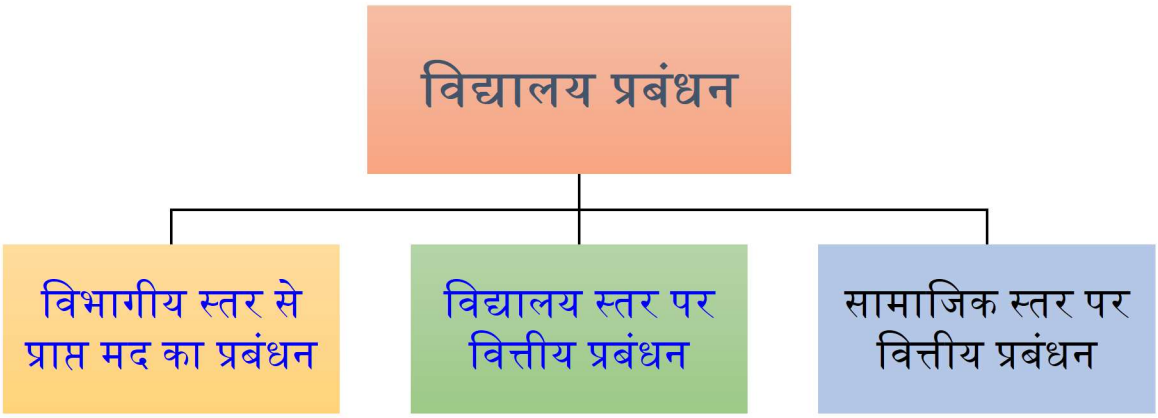

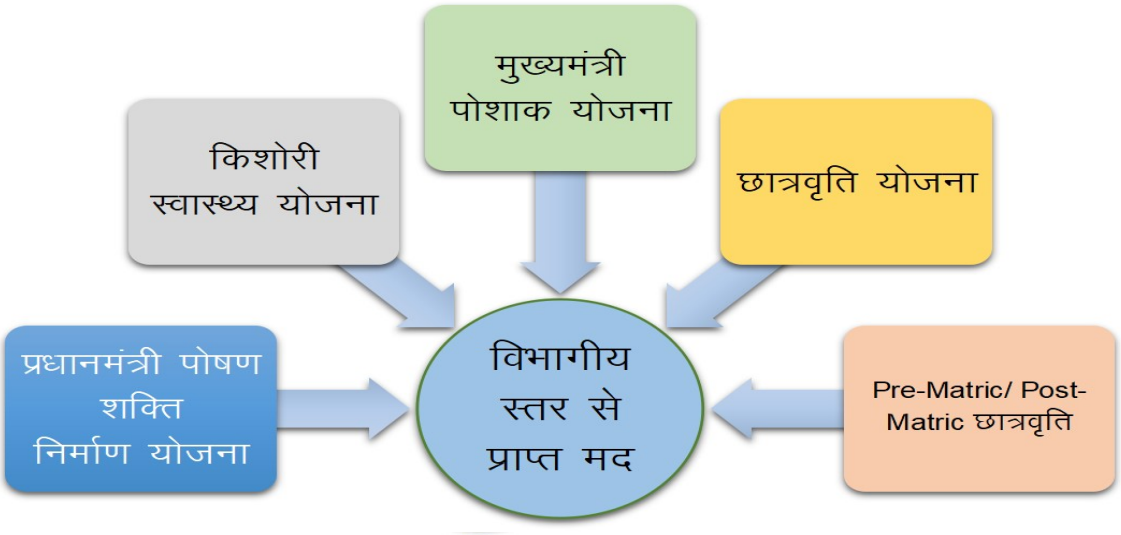
मुख्यमंत्री पोशाक योजना
किशोरी स्वास्थ्य योजना
छात्रवृति योजना
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
विभागीय स्तर से प्राप्त मद
Pre-Matric/ Post-Matric छात्रवृति

शिक्षक
विद्यालय
छात्र
विद्यालय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन

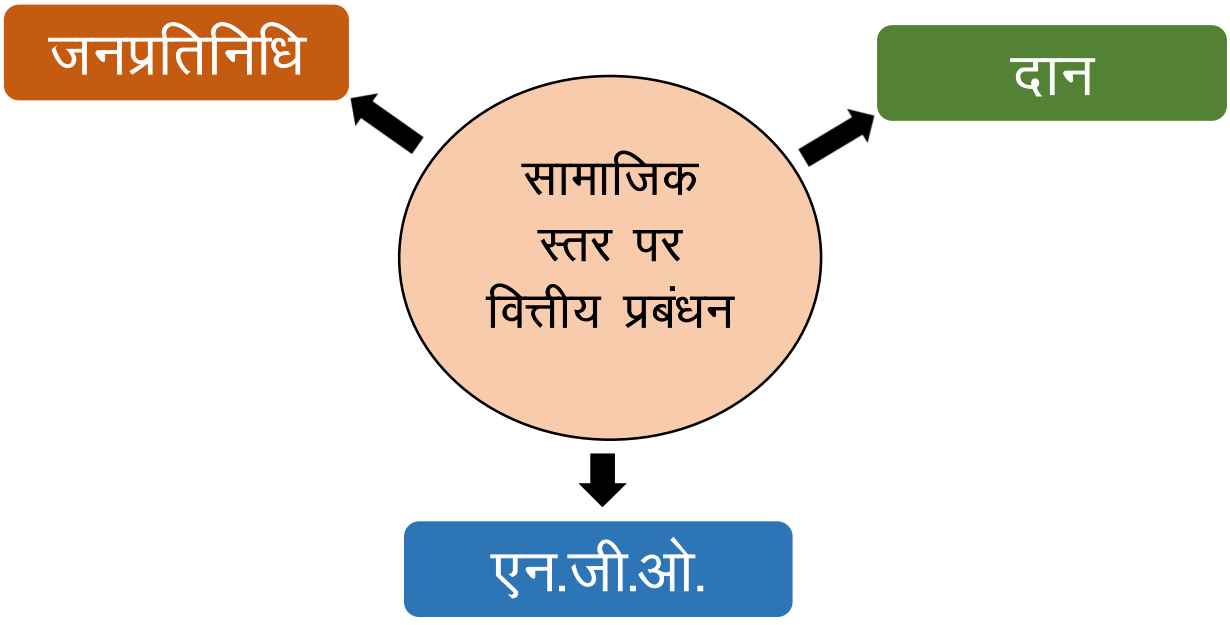
जनप्रतिनिधि
दान
सामाजिक स्तर पर वित्तीय प्रबंधन
एन.जी.ओ.

विद्यालय के पास स्वयं के कई वित्तीय स्रोत उपलब्ध होते हैं, लेकिन उचित प्रबंधन एवं जानकारी के अभाव में विद्यालय उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।

विद्यालय के पास उपलब्ध स्त्रोत

- व्यावसायिक आवासीय भूमि
- कृषि योग्य भूमि
- विकास कोष

व्यावसायिक / आवासीय भूमि

बिहार राज्य अंतर्गत कई विद्यालय हैं जिनके पास भवन के अतिरिक्त व्यावसायिक तथा आवासीय भूमि है जिसका स्थानीय स्तर पर प्रबंधन कर आर्थिक स्रोत विकसित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो जानकारी के अभाव में इसका उपयोग नहीं करते हैं। वैसे विद्यालयों को प्रेरित कर आर्थिक स्रोत विकसित किया जा सकता है तथा इससे विद्यालय में विकासात्मक कार्य किये जा सकते हैं। जैसे-आवश्यकता अनुरूप संसाधन पर व्यय इत्यादि।

केस स्टडी

विद्यालय विकास में आर्थिक संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना आर्थिक संसाधन के विद्यालय के भौतिक संरचना, शैक्षिक संसाधन, वातावरण निर्माण की कल्पना अधूरी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को छात्र संख्या के अनुपात में समग्र शिक्षा की राशि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई जा रही है,लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जहां यह राशि पर्याप्त नहीं है। वैसे विद्यालय समुदाय, एन.जी.ओ., स्व संसाधन विकसित कर विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

कैमूर जिला अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय डहरक, अंचल रामगढ़ द्वारा विद्यालय भवन के अतिरिक्त भूमि का उपयोग अतिरिक्त कमरा निर्माण कर दुकान हेतु आवंटित किया गया है, जिससे विद्यालय को आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन की सकारात्मक सोच से ग्रामीण द्वारा स्वयं के राशि से कमरे का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत की राशि प्रत्येक माह निर्धारित मासिक किराया में अंशदान के रूप में कटौती की जाती है तथा शेष राशि विद्यालय को किराया के रूप में आवंटित दुकानदार द्वारा जमा की जाती है। विद्यालय को प्राप्त राशि से वार्षिक कार्य योजना निर्माण कर आवश्यक कार्य कराया जाता है। राशि का लेखा संधारण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय की भव्यता एवं आकर्षण एक मिसाल पेश कर रहा है।

यदि इस प्रकार अन्य विद्यालय अपने व्यावसायिक एवं आवासीय भूमि का उपयोग करें तो निश्चित रूप से विद्यालय आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है।

कृषि योग्य भूमि

कई विद्यालयों के पास अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसकी बंदोबस्ती कर विद्यालय अपनेआर्थिक संसाधनों को मजबूत कर रहे हैं, फिर भी कतिपय विद्यालय जानकारी न होने तथा विभागीय प्रक्रिया जटिल होने के कारण अपने भूमि की बंदोबस्ती नहीं कर आर्थिक क्षति उठा रहे हैं l इस संदर्भ में आवश्यक हो जाता है की पूरी प्रक्रिया की जानकारी विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि अपने परिसंपत्तियों का प्रबंध स्थानीय स्तर पर विद्यालय कर सकें एवं विद्यालय उसका उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार कर सके।

NEP 2020 में निहित प्रावधान एवं कौशल विकास संबंधित शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार के कृषि योग्य भूमि का उपयोग विद्यालय द्वारा करने के लिए प्रेरित करने पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।

योजनाबद्ध तरीके से समुचित प्रबंधन कर भूमि की एक-एक हिस्से का सदुपयोग संभव है l विद्यालय के साथ-साथ विभाग को पहल करने एवं योजना निर्माण में सहायता करने की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी द्वारा स्थापित **बुनियादी विद्यालय** की परिकल्पना में भी यह बात सन्निहित थी, कालांतर में निष्क्रियता के कारण योजना अस्तित्व विहीन होती जा रही है।

NEP2020 द्वारा एक बार पुनः इसे पुनर्जित करने में सहायता प्राप्त होगा।

विकास कोष

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास अपना विकास कोष होता है जिसके संचित निधि के उचित प्रबंधन से विद्यालय सतत् विकास के क्षेत्र में अग्रसर हो सकता है l

विकास कोष का प्रबंधन

- शिक्षण एवं गैर शिक्षण मानव बल उपलब्ध कराने में
- भौतिक संसाधन में
- यातायात सुविधा प्रदान करने में
- अन्य आवश्यक कार्यों में

केस स्टडी

आधारभूत संरचना का विकास

शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचना की उपलब्धता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों का सहयोग लेने का निश्चय किया। इस हेतु प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सह विधायक एवं विभिन्न गांव के बुद्धिजीवियों से बात किया। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोग विद्यालय को आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार हुए। इस तरह से एक संस्था अस्तित्व में आई जिसे GUARDIAN GOVERNMENT' नाम दिया गया। इसका नारा है "इंतजार नहीं इंतजाम करेंगे"। आरंभ में अनियमित आर्थिक सहयोग प्राप्त होता था किंतु धीरे-धीरे विश्वास बढ़ने के साथ हीं यह नियमित रूप से प्राप्त होने लगा। इस राशि के खर्च की एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई। इस राशि से विद्यालय में निम्नलिखित काम किया गया है-

1. दो कमरों का निर्माण एवं आवश्यक मरम्मत का कार्य ।
2. अभिभावक शिक्षकों की व्यवस्था विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी क्योंकि विद्यालय में छात्राओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। अभी विद्यालय में करीब 2300 छात्राएं नामांकित हैं। गार्जियन गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालय में 14 अभिभावक शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। हम लोग इसमें स्थानीय लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं जो नजदीक के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से पास हुई होती है। उन्हें एक अल्पकालिक रोजगार भी मिल जाता है और विद्यालय में शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाती है।
3. कम्प्यूटर की व्यवस्था इसी राशि से हमने विद्यालय में 22 कंप्यूटर लगवाया है। विद्यालय की छात्राएं नियमित रूप से कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

यह **गार्जियन गवर्नमेंट** विद्यालय के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है।

जनप्रतिनिधियों से सहयोग विद्यालय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने से जनप्रतिनिधियों ने भी विद्यालय को भरपूर सहयोग किया। उनके सहयोग से विद्यालय में निम्नलिखित विकास का कार्य हुआ

1. विद्यालय में 6 नये कमरों का निर्माण कराने में सफल रहा ।
2. 20 सुसज्जित टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया।
3. पर्याप्त बेंच डेस्क बनवाए गए।
4. शुद्ध पेयजल हेतु बड़ी क्षमता का RO विद्यालय में लगाया गया ।
5. चार मंजिले वर्ग कक्षों तक पहुंचने हेतु लिफ्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है।
6. जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय को 5 बसें प्रदान की हैं। जिन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलाए जा रहा है।

आदर्श बालिका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, कैमूर

मूल्यांकन हेतु प्रश्न

- भूमि बंदोबस्ती कौन अधिकारी करते हैं?
- जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होते हैं?
- अभिभावक विद्यालय को किन–किन रूपों में मदद कर सकते हैं?
- गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) विद्यालय को किस माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं?
- विद्यालय के आर्थिक संसाधन को कैसे मजबूत बना सकते हैं?
- प्रमण्डल स्तर पर शिक्षा विभाग का नियंत्री पदाधिकारी कौन होते हैं?

000

डिजाइन एवं ग्राफिक्स : रवि रौशन कुमार